आम जनता के काम रुके, करनाल में सीएमओ का पद खाली रहना मतलब कुछ तो गड़बड़ है

करनाल : (आकर्षण) हरियाणा में करनाल शहर बेशक सीएम सिटी के नाम से विख्यात हो रहा है लेकिन यहां के हालात आम शहरों की तरह ही है। यदि बात प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर करें तो जैसे हालात वर्ष 2014 में करनाल के सीएम सिटी बनने से पहले थे आज भी उनमें कोई बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिल रहा।

खबर है कि करनाल से एक बार फिर कुछ ही महीने पहले ट्रांसफर होकर आए सिविल सर्जन डॉ गुलशन अरोड़ा को ट्रांसफर कर दिया गया है। हम सवाल इस पर तो नहीं उठाएंगे कि ट्रांसफर क्यों हुआ? लेकिन ट्रांसफर जिस तरह हुआ वो बेहद चौंकाने वाला विषय है। अक्सर जब भी किसी अधिकारी को बदला जाता है तो उसकी जगह किसी नए अधिकारी को नियुक्ति दे दी जाती है लेकिन सीएम सिटी करनाल जैसे महत्वपूर्ण शहर में ऐसा नहीं हुआ।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करनाल में इस समय कोई भी अधिकारी सिविल सर्जन नहीं बनना चाहता? कारण साफ है कि सीएम सिटी में राजनीतिक और प्रशासनिक लाबी केवल उसी अधिकारी की नियुक्ति करवाना चाहती है जो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह सके। खबर तो ये भी है कि करनाल में जनता के काम से ज्यादा सीएमओ को नेताओं को खुश करने के लिए काम करने को मजबूर किया जाता है।

जिन लोगो की बात हम कर रहे है उसमें भाजपा के दो बड़े नेता शामिल हैं तो एक अधिकारी इसी पेशे से जुड़ा हुआ है जो सीएम सिटी में लम्बे समय से सेटिंग के बलबूते अभी तक पैर जमाकर बैठा है। ये अधिकारी कांग्रेस राज में भी करनाल में था और आज जब भाजपा सरकार को 4 साल से अधिक का समय हो चुका हो चुका है तब भी श्रीमान जी करनाल में ही जुटे हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार बेशक बदल गई हो लेकिन व्यवस्था और समीकरण अभी भी पुराने ही हैं क्योंकि रैलियों में ईमानदारी के दावे कितने भी हों लेकिन हर सरकार में गांधी जी सभी को अच्छे लगते है।

सूचना तो यहां तक है कि अपने अपने बन्दों को एडजस्ट करने को लेकर भाजपा नेताओं में ही तलवारे खिंची हुई हैं और बदला लेने की नीयत से आये दिन अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कोई सीएम को कहता है कि ये अफसर मेरे काम नहीं करता तो कोई कहता है ये जनता के काम नहीं करता। सीएम भी शायद कान के कच्चे हैं इसीलिए बिना नफा नुकसान देखे ट्रांसफर के आदेश दे देते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल सम्भव नहीं है कि किसी बड़े अफसर का तबादला सीएम सिटी से बिना सीएम की सहमति से हो जाये?

अब सवाल है, क्या सीएम मनोहर लाल खट्टर इन सबसे अनजान हैं या वो अपनी किचन कैबिनेट से मुंह की बिगाड़ना नहीं चाहते? लेकिन लोग रह रह कर सवाल दाग रहे है कि आखिर मनोहर लाल खट्टर जो नगर निगम चुनाव में खुद को पंजाबियों का सबसे बड़ा नेता बताकर करनाल की जनता का वोट लेकर चलते बने करनाल में इसी समुदाय के अधिकारियों पर अत्याचार क्यों करवा रहे हैं या करने की छूट दे रहे हैं? ये बात किसी से छुपी नहीं है कि करनाल के दो पूर्व सिविल सर्जन पंजाबी समुदाय के ही थे। विभागीय सूत्र बताते है कि इन दोनों अधिकारियों को भाजपा नेताओं के आपसी कलह के कारण उनके पदों से रुखसत करवा दिया गया।

जनता खट्टर सरकार में ही बिजली विभाग के एक्सईएन सुरेन्द्र पर हुए उस राजनीतिक बदले को भी भूली नहीं है जिन्हें एक अधिकारी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए न केवल करनाल से ट्रांर्सफर कर दिया था बल्कि उन्हें कई मामलो में फंसाने के प्रयास भी किया गया था? सूत्रों की माने तो ये पूरा प्रकरण तब हुआ था जब करनाल के बड़े-बड़े राजनीतिक और सामाजिक लोग सीएम मनोहर लाल खट्टर से एक्सईएन सुरेन्द्र का तबादला रुकवाने को लेकर मिले थे लेकिन इस बड़े अधिकारी ने सीएम को ये कहकर तबादला करने से मना कर दिया था कि यदि को करनाल लाना है तो पहले मुझे ट्रांसफर कर दो, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने हाथ खींच लिए थे। आज भी जब इन कुछ मुद्दों की चर्चा होती है तो भाजपा नेता हमें बैकफुट पर ही नजर आते हैं।

सुधी पाठकों से अपील

31 वर्षों से 'मज़दूर मोर्चा' वैकल्पिक मीडिया के तौर पर अपने सुधी पाठकों को वह समाचार, विचार एवं जन उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता आ रहा है जिसे अन्य मीडिया छिपाने का प्रयास करता है। सुधी पाठक इतना तो समझ ही गये होंगे कि यह छोटा सा अखबार किसी भी राजनीतिक अथवा व्यवसायिक धड़े से जुड़ा नहीं है। जनहित में जो भी प्रकाशित करने लायक सामग्री हो पाती है उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

बिना विज्ञापनों के, केवल पाठकों के सहयोग से चलने वाला यह छोटा सा अखबार आपको और अधिक बेहतर व निरंतर सेवा देता रहे इसके लिये आप से निवेदन है कि इसमें अपना आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। 'मज़दूर मोर्चा' नियमित रूप से खरीदकर पढ़ने वाले पाठक तो अपना योगदान दे ही रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अखबार पढ़ने वाले पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करें। वार्षिक सहयोग के तौर पर 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की धनराशि सामर्थ्य अनुसार 'मज़दूर मोर्चा' के निम्नलिखित खाते में डाले जा सकते हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में

खाता संख्या : 451102010004150

IFSC CODE : UBIN0545112

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **आनंद मैगजीन सैंटर केसी रोड, एनएच-5**
2. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड**
3. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
4. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे**
5. **राम खिलावन बल्लबगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने**
6. **हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास**
7. **जितेन्द्र, बाटा सैंटर - 9971064207**

गतांक की चीर-फ़ाड़

लोकतंत्र में हर प्रक्रिया का दीवाला

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 27 जनवरी-2 फ़रवरी 2019 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) व हिन्दुत्ववादियों ने स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया। परंतु आजकल आरएसएस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान को भुनाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिन्दुत्ववादी विचारक वी डी सावरकर को महान देशभक्त बताते हुए उनका गुणगान करते हैं, जबकि सावरकर ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फ़ौज व नेताजी के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की सहायता की तथा लाखों हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाया। उस समय नेताजी देश की आज़ादी के लिये विदेशी समर्थन जुटाने के कोशिश कर रहे थे और आज़ाद हिंद फ़ौज को पूर्वोत्तर भारत में सैनिक अभियान के लिये लामबंद कर रहे थे। प्रधानमंत्री के चरित्र के इस विरोधाभास का 'नेताजी के खिलाफ़ अपराधों के लिये माफ़ी मांगे हिन्दुत्ववादी' में पुरा खुलासा किया गया है।

हिन्दू महासभा व आरएसएस के दस्तावेज़ों से स्पष्ट है कि सावरकर व एमएस गोलवलकर दोनों का दृढ विश्वास था कि ब्रिटिश साम्राज्य कभी नहीं हारेगा और अंग्रेज शासकों के साथ दोस्ती करने में ही उनकी हिन्दुत्ववादी राजनीति का भविष्य निहित है। गौरतलब है कि जब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर अंग्रेजों को युद्ध में विजयी बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन का पंमुख नारा 'न एक भाई न एक पाई' बुलंद करते हुए हज़ारों भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का भयंकर उत्पीड़न सहा था। 'मज़दूर मोर्चा' का यह अंक इतिहास में रूचि रखने वाले पाठकों के लिये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन उद्धृत दस्तावेज़ों व तथ्यों का विवरण इतिहास की सामान्य पुस्तकों में नहीं मिलता है।

कच्चे तेल का आयात बिल देश के सबसे बड़े खर्चों में शुमार होता है। मोदी सरकार के साढे चार साल के कार्यकाल में कच्चे तेल की कीमत यूपीए के काल से आधे से भी कम होने से मोदी सरकार को बेतहाशा लाभ हुआ। वाट्सएप यूनिवर्सिटी में मोदी समर्थकों ने प्रचार किया कि मोदी जी ने सारा विदेशी कर्ज़ चुका दिया और कोई नया कर्ज़ भी नहीं लिया, लेकिन इस झूठे प्रचार की 'मोदी के साढ़े चार साल के कार्यकाल में भारत सरकार पर 49 फ़ीसदी कर्ज़ बढ़ा है' में पोल खोली गई है। केन्द्र सरकार द्वारा कर्ज पर जारी स्टेट्स रिर्पोट के अनुसार जून 2014 में मोदी सरकार पर कुल कर्ज़ 54,90,763 करोड़ रुपये से बढकर सितम्बर 2018 में 82, 03,253 करोड़ रुपये हो गया।

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों की नारजगी कम करने के लिये मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये जल्दबाज़ी में संविधान संशोधन और आरक्षण का बिल पारित करा लिया और लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक हितों के मद्दे नज़र इसका समर्थन किया। आरक्षण की संवैधानिक स्थिति का 'सवर्णों को 10 फ़ीसदी आरक्षण: संजीव खुद शाह' में विश्लेषण किया गया है। ध्यान देने योग्य है कि सवर्णों ने आरक्षण की मांग कभी नहीं उठाई व आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कभी नहीं रहा तथा आरक्षण सामाजिक रूप से दलित व पिछड़ी जातियों को ही दिया जाता है। दरअसल सवर्णों को आरक्षण देने की मोदी सरकार व संघ परिवार की यह एक दूरगामी रहस्यमय कवायद है कि यदि यह कानून अदालल की परीक्षा से सफ़लतापूर्वक निकल जाता है तो आगे चलकर इस आरक्षण पद्धति में बड़ा बदलाव किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर मोदी सरकार ने सवर्णों को मात्र एक झुनझुना पकड़वाया है। जब रोज़गार के अवसर ही उपलब्ध नहीं है तो आरक्षण से किसको रोज़गार मिलेगा और निजी शिक्षण संस्थाओं में फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि वहां ग़रीब सवर्ण कैसे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त गरीब सवर्ण की आय सीमा 8 लाख रुपये वार्षिक निर्धारित की है। इस सीमा में सवर्णों की लगभग 90 प्रतिशत आबादी आ जाती है। सोचने वाली बात है कि इस आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा?

लोकसभा चुनाव के मद्देनज़ केन्द्र व राज्यों की भाजपा सरकारों द्वारा बेरोज़गार युवाओं को लुभाने के लिये नई भर्तियों की घोषणा की जा रही है लेकिन व्यवहारिता में कोई रोज़गार मॉडल ही नहीं है। मोदी-योगी-खट्टर सरकारों द्वारा बेरोज़गार युवाओं को भ्रमित किए जाने का 'रोजगार मोदी की चुनाव घोषणा में' में उजागर किया गया है।

हरियाणा में खट्टर ने अपने कार्यकाल में रोजगार के कोई नए अवसर उपलब्ध नहीं करवाए, परंतु अब विभिन्न विभागों में कान्ट्रैक्ट आधारित 15000 से अधिक कार्यरत कर्मियों के स्थान पर 18000 ग्रुप डी की नौकरियां दी जाएंगी। नए रोज़गार उपलब्ध कराने की बजाए 15000 हज़ार को निकालकर 18000 को लिया गया। 'हरियाणा में बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक-18000 ग्रुप डी की नौकरियां देकर 15000 संविदा नौकरियां समाप्त करेंगे खट्टर' में हरियाणा के रोज़गार मॉडल का पर्दाफ़ाश किया गया है। अब तुर्रा यह है कि खट्टर सरकार इन खोखले दावों की वाहवाही करने वाले विज्ञापन जारी किये गए हैं।

लोकतंत्र में निर्वाचन की प्रक्रिया विशेष महत्व रखती है। विदेशों में राजनीतिक दलों के अध्यक्ष का चुनाव वाकायदा नियमित रूप से होता रहता है। परंतु भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों-भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी दल, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, शिव सेना, लोक जनशक्ति पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, डीएमके, एआईएडीमके, टीडीपी, टीआरएसएस आदि में निर्वाचन प्रणाली का स्थान मनोनयन प्रणाली ने ले लिया है, जिसकी 'भारत के किसी भी दल में नहीं है आंतरिक लोकतंत्र' में समीक्षा की गई है। इस मामले में कम्यूनिस्ट पार्टियां अपवाद हैं। हालांकि कांग्रेस में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनने के लिये चुनाव का सामना करना पड़ा है।

भारत के सभी राजनीतिक दल परिवारवाद रोग से भी ग्रस्त हैं, जिससे राजनीति चंद परिवारों तक सिमट कर रह जाती है। किसी भी राज्य में उपचुनाव में अक्सर वहां की सत्तारूढ पार्टी की विजय होती है क्योंकि उस उपचुनाव को जीतने के लिये सरकार द्वारा पूरे संशाधन व सरकारी मशीनरी तथा पूरा मंत्रीमंडल झोंक दिए जाते हैं। यही हाल जींद उपचुनाव का हुआ है। कांग्रेस, इनैलो व भाजपा के जाट प्रत्याशियों के विरुद्ध भाजपा द्वारा गैरजाट प्रत्याशी खड़ा करने से भी भाजपा का पलड़ा भारी हुआ है, जिसका 'जिंद उपचुनाव में कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है फ़ेल' में उचित आंकलन किया गया है। रहस्यमय है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला को क्यों उतारा भाजपा के कृष्ण मिड्ढा ने जजपा के दिग्विजय सिंह चौटाला को पराजित कर विजय प्राप्त की जबकि सुरजेवाला तीसरे स्थान पर रहे और सबसे बड़ा झटका इनैलो को लगा।

चुनाव आयोग द्वारा तय खर्च की अधिकतम सीमा चुनाव प्रक्रिया चालू होने के बाद ही लागू होती है जिसका फ़ायदा धनी व सम्पन्नशील व्यक्ति उठाते हैं। क्योंकि विधायक एवं राज्य के उद्योगमंत्री विपुल गोयल चुनावी मोड़ में आ चुके हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने के लिये अपनी थैलियों के मुंह खोल दिये हैं जिसका 'मंत्री विपुल गोयल की चुनाव तैयारी पैसों के दम पर' में कच्चा चिट्ठा खोला गया है। जागरूकता के आभाव में गरीब लोग गरीबी को भगवान की देन व भाग्य का लेख मानते हैं। परन्तु यह नहीं समझ पाते कि सत्ता के बल पर ही विपुल गोयल जैसे चंद लोग अमीर से अमीर जबकि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का जनरल सैक्रेटरी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त करने पर 'कांग्रेस ने प्रियंका को चुनाव परिदृश्य में लाकर गंगा पुत्र को बनारस छोड़कर भागने का रास्ता बंद कर दिया है' नरेन्द्र मोदी के 12 साल गुजरात का मुख्यमंत्री तथा साढे चार साल प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ते लेने के बावजूद मोदी जी के माता के गरीब ही रहने पर '12 साल मुख्य मंत्री की, साढे चार साल प्रधानमंत्री का वेतन लेने के बावजूद जिसकी मां गरीब ही रहती है उस बेटे को क्या कहेंगे...? तथा सैयद सूजा द्वारा इंग्लैंड में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम का हैककर 214 लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिताने पर 'ईवीएम हैक कर जीते थे, 2014 चुनाव हेकर' द्वारा प्रधानमंत्री मोदी तथा मोदी सरकार पर उपयुक्त कटाक्ष किया गया है।